









# सेवा भाव से योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाना सुनिश्चित करें : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ समाज के वंचित वर्ग के कल्याण हेतु समर्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार को योजनाओं का लाभ समाज के कमजोर वर्ग को मिलना सुनिश्चित हो इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सेवाभाव से कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम पंचतक के व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागीय बजट घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे तथा अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न ले पाए, क्योंकि इससे पात्र व्यक्ति के हितों पर कुटाराघात होता है। शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता तय कर चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पथर तोड़ने एवं पीसने के कार्य वाले स्थानों एवं खदानों पर निर्धारित गाईडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराए ताकि सिलिकोसिस रोग पर नियंत्रण किया जा सके।

- राज्य में 90 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए 1500 करोड़
- मुख्यमंत्री ने की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई निर्णय किए हैं। राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए एससीएसपी एवं टीएसपी फंड की राशि को 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये किया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि

आश्रय से वंचित घूमंतू समुदाय के लोगों के लिए घूमंतू आवासीय योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के दिव्यांग नागरिकों को कुत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही, 2 हजार युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने के लिए स्कूटी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना प्रारंभ कर 5 हजार रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार लगभग 90 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की पात्रता व उनसे जुड़े रिकॉर्ड का नियमित रूप से सत्यापन करें और इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे पेंशनर्स की मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य कर संबंधित कार्मिकों को जिम्मेदारी तय की जाए।

# महाराणा प्रताप ट्यूरिस्ट सर्किट व ब्रज चौरासी यात्रा पर प्रस्तुतिकरण



उपमुख्यमंत्री दिवा कुमारी के समक्ष सोमवार को पर्यटन भवन में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष अंकार सिंह लखावत तथा पर्यटन शासन सचिव रवि जैन की उपस्थिति में "महाराणा प्रताप ट्यूरिस्ट सर्किट" और "ब्रज चौरासी यात्रा की" कॉन्सेप्ट प्लान और पार्लियामेंट्री रिपोर्ट बनाने के लिए प्राप्त निविदाओं का कन्सल्टेन्ट्स व आर्किटेक्ट्स ने प्रस्तुतिकरण दिया।

# नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जयपुर फुट की कार्य प्रणाली जानी

जयपुर। जी-20 में भारत सरकार के निजी प्रतिनिधि और नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने जयपुर फुट की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया।



जी-20 में भारत सरकार के निजी प्रतिनिधि और नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने जयपुर फुट की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया।

फुट जैसे गुणवत्ता वाले उपकरण और अधिक प्रचलित हों और अधिक से अधिक विकलांगों द्वारा अपनाये जाये। अमिताभ कान्त ने दस विकलांगों के पुर्नवास और उन्हें जयपुर फुट लगाने के लिए योगदान दिया।

# 'मस्जिदों को मंदिर बता कर झूठे केस दायर किये जा रहे हैं'

जयपुर। राजस्थान के अजमेर और उत्तर प्रदेश के संभल मामले को लेकर आज मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए। मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी ने कहा कि धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने का धिनीना काम किया जा रहा है। देश के आपसी सद्भाव को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। मस्जिदों को मंदिर बता कर अदालत में झूठे केस दायर किया जा रहे हैं। सर्वे के नाम पर मस्जिदों के स्टेज को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर होने के बनावे सर्वे करा कर देश का माहौल खराब किया गया। केन्द्र सरकार बकम संशोधन बिल लाकर मुस्लिम को जमीनों को हड़पना चाहती है। संबल मामले में जिस तरह से मस्जिद को बचाने अंग्रेजों को देश की आजागी को उठाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ इस

अजमेर दरगाह और संभल मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस

दौरान पांच युवाओं की हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब की दरगाह ईसानियत और भाईचारे का संदेश देती है, और ऐसे पवित्र स्थलों पर विवाद पैदा करना गलत है। अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह को धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि सरकार बकम संशोधन बिल लाकर मुस्लिम को जमीनों को हड़पना चाहती है। संबल मामले में जिस तरह से मस्जिद को बचाने अंग्रेजों को देश की आजागी को उठाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ इस

# प्रधानमंत्री विशाल जनसभा में ई.आर.सी.पी. परियोजना का शिलान्यास करेंगे : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई दिल्ली स्थित आवास पर पत्रकारों के साथ यूसीसी, कृषक मित्र भाजपा सरकार, अवैध धर्मोन्तपन और राजस्थान में भाजपा सरकार के कार्यों पर चर्चा की। राठौड़ ने कहा कि केंद्र और राजस्थान में भाजपा की सरकार लगातार जनहितैथी कार्यों को कर रही है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा जहां समान नागरिकता कानून का समर्थन किया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा ईआरसीपी योजना को मूर्त रूप देकर लाखों किसानों के लिए सिंचाई

परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेशभर से करीबन तीन लाख लोगों की उपस्थिति रहेगी

राठौड़ ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना का प्रारूप 2015-16 में तैयार किया गया, इसके बाद प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को अटकाने का काम किया हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता में आने के साथ ही मध्यप्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस जीवन दायनी परियोजना पर कार्य शुरू किया और अब इसका शिलान्यास होगा। परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेशभर से करीबन तीन लाख लोगों की उपस्थिति रहेगी। इससे जहां पीने के पानी की

समस्या का समाधान होगा, वहीं सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त जल भी मिलेगा। राठौड़ ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि विपक्ष को सकारात्मक कार्यों में अड़चन पैदा नहीं करनी चाहिए। हालांकि विपक्ष का कार्य आरोप प्रत्यारोप लगाना ही रह गया है। भाजपा ने प्रदेश की जनता के लिए ईआरसीपी, पीकेसी के साथ जवाब ई पुर्नभरण योजना पर भी कार्य शुरू किया। इसके साथ प्रदेश के बांध, नहरों के पुर्नभरण सहित अन्य विकास के कार्यों को प्राथमिकता से किया जा रहा है।

# मुख्यमंत्री ने अनुशासनहीन नौ कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी

जयपुर। राज्य सरकार राजकीय कार्यालयों में जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस विभाग के 9 अनुशासनहीन कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय किया है। यह निर्णय राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 53 (1) के प्रावधान के तहत पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित रिज्यू कमेटी एवं प्रशासनिक सुधार की आज्ञानुसार गठित उच्च स्तरीय स्थायी समिति की अनुशंसा पर किया गया है। इन कार्मिकों ने घोर लापरवाही करते हुए अनुशासनहीनता एवं अनियमितताएं की थी, जिसके लिए पूर्व में उन्हें कई बार दंडित भी किया गया था।

# भजनलाल सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करें : डॉ. प्रेमचंद बैरवा

जयपुर (कासं)। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को शासन सचिवालय में राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, आयुर्वेद विभाग की तैयारियों की समीक्षा की।



उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की।

विविध उपलब्धियों के समीप, आयुर्वेद विभाग प्रचार-प्रसार के लिए प्रमुख स्थानों पर विशेष होर्डिंग्स लगाए जाएं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं

# बजरी की अवैध सप्लाई के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी

जयपुर। प्रदेश में बजरी की बढ़ती दरों के लिए राज्य सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। शहर में बजरी मंडियों में अवैध बजरी सप्लाई को लेकर व्यापारी लामबंद हो गए हैं।

अगर नशासन ने रोक नहीं लगाई तो सप्लाई बंद कर देंगे : नवीन शर्मा

नदी क्षेत्र में वैध बजरी खनन के लिए समय पर लीज जारी नहीं की जा रही है जिसके कारण अवैध बजरी खनन को बढ़ावा मिल रहा है। यह बात ऑल राजस्थान बजरी टुक ऑपरेटर वैलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष नवीन शर्मा ने आरोप लगाया कि अवैध बजरी खनन को बढ़ावा देने के लिए पुलिस प्रशासन वैध रक्वा के साथ बजरी परिवहन करने वाले टुक ऑपरेटर्स को परेशान कर रही है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध बजरी खनन व परिवहन बंद नहीं किए जाने पर सभी टुक ऑपरेटर्स बजरी परिवहन बंद कर देंगे। नवीन शर्मा ने कहा कि अवैध

बजरी परिवहन को बंद करवाने के लिए लाइसेंस धारक व्यापारियों ने इस संबंध में आज खान विभाग के अधिकारियों को पत्र देकर इसे रोकवाने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर वैध बजरी खनन क्षेत्रों से खनन बंद करने और सप्लाई रोकने की चेतावनी दी है। टॉक, सवाई माधोपुर एरिया में कई ब्लॉक में अवैध बजरी का खनन हो रहा है। उन खनन एरिया के आसपास रिमोट एरिया (गांवों में) बजरी के अवैध स्टॉक बनाए जा रहे हैं। इन स्टॉक में अवैध तरीके से खनन करके बजरी एकत्रित किया जा रहा है उसे जयपुर शहर

को प्रदर्शित करते हुए गंगीन सचिव बुकलेट का मुद्रण एवं जन सामान्य तक वितरण सुनिश्चित कर ताकि अधिकतम जन-जन तक विभागीय उपलब्धियों की जानकारी पहुंच सके। डॉ. बैरवा ने कहा कि विभागीय उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रमुख समाचार पत्रों, ऑडियो एवं वीडियो फिल्म के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जाए। बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अध्यक्ष शुभा सिंह, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की शासन सचिव डॉ. आरूपी अजेय मलिक, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की आयुक्त एवं सड़क सचिव शुचि त्यागी, रोडवेज प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा, मीडिया सलाहकार आनंद शर्मा सहित अन्य उच्चाधिकारी मौजूद थे।

उपलब्धियों के शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया और प्रमुख चौराहों पर डिजिटल एलईडी पैनल पर प्रदर्शित होंगे

'जून 2025 के बाद निर्मित एन-2 और एन-3 श्रेणी के ट्रकों के कैबिन में चालकों की सुविधा के लिए शुरू होगी वातानुकूलन प्रणाली'

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने दी जानकारी

राठौड़ बताया कि केंद्र सरकार देश में निजी टुक वाहनों में चालकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के साथ चालक की थकान की समस्या का समाधान करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जून 2025 के बाद निर्मित एन-2 और एन-3 श्रेणी के वाहनों में चैसिस निर्माताओं द्वारा निर्धारित आईएस के अनुसार वातानुकूलन प्रणाली के लिए एक अनुमोदित किट की आपूर्ति भी की जाएगी, जिससे बांडी तैयार करने वालों को किट लगाने की सुविधा हो सके। इससे टुक चालकों के कैबिन में वातानुकूलित सुविधा शुरू हो जाएगी।





